हड़कंप | अवैध शराब का जखीरा पकड़ा, आबकारी विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे

एसडीएम की छापामार कार्रवाई ने खोली आबकारी विभाग की पोल

नवभारत उमरिया 14 मई। जिले के फजिलगंज में हाल ही में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बांधवगढ़, अम्बिकेश प्रताप सिंह ने जो दबिश दी, उसने जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप तो मचा दिया, लेकिन साथ ही कई ऐसे शर्मनाक सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब देने में आबकारी विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं।

कलेक्टर राखी सहाय के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में एसडीएम सिंह ने अपनी बहादुरी और सक्रियता का परिचय देते हुए अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। पूरे जिले में उनकी तारीफ हो रही है। जनसंपर्क विभाग ने भी ढोल-नगाड़े बजाते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन एसडीएम इस चमक-धमक वाली विज्ञप्ति के पीछे का असली अंधेरा देखना भूल गए या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया?

43 लीटर जहर और सेटिंग का खेल

मौके से व्हाईट फॉक्स वोडका, देशी प्लेन, 8 पीएम, इम्पीरियल ब्लू और बियर सहित कुल 43 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई। खाली बोतलों का ढेर गवाही दे रहा था कि यहां लंबे समय से महफिल सज रही थी। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन केवल छोटे प्यादों (पैकारों) को बलि का बकरा बनाकर इतिश्री कर लेगा, असली गुनहगार तो वो ठेकेदार हैं जो अपनी दुकान के स्टॉक का दुरुपयोग कर अवैध पैकारी को बढ़ावा दे रहे हैं।

कुंभकर्णी नींद में सोया सफेद हाथी

आश्चर्य और घोर शर्म की बात तो यह है कि जिले में एक पूरा का पूरा आबकारी विभाग तैनात है। दफ्तरों में फाइलें दौड़ रही हैं, निरीक्षकों को गाडियां और वेतन मिल रहा है, ताकि वे अवैध शराब रोक सकें, लेकिन फजिलगंज की पुरानी भट्टी में दो-दो कमरों में शराब का बार चल रहा था, लोग बैठकर जाम छलका रहे थे और आबकारी विभाग के नुमाइंदों को भनक तक नहीं लगी या फिर भनक तो थी, लेकिन महीने की चढ़ोत्तरी ने उनकी जुबान और जमीर दोनों पर ताला जड़ रखा था?

जहां से बहती है अवैध शराब की गंगा

एसडीएम की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए आरोपी राजेश सिंह ने सरेआम कबूला कि वह यह शराब बस स्टैंड की भट्टी से लाता है। यह प्रमाणित हो गया है कि लाइसेंसधारी शराब ठेकेदार अपनी दुकानों से अवैध पैकारी (सप्लाई) करवा रहे हैं। सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बस स्टैंड की दुकान से शराब निकालकर गली-मोहल्लों में मौत का सामान परोसा जा रहा है, लेकिन मजे की बात देखिए, प्रशासन की सफेद प्रेस विज्ञप्ति में इस बस स्टैंड की भट्टी और उसके रसूखदार मालिक के खिलाफ कार्रवाई का कहीं कोई ठोस जिक्र नहीं है।

जनसंपर्क के ढोल और हकीकत के बोल

प्रशासन ने दावा किया है कि अवैध मदिरा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक सप्लाई देने वाले मुख्य ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त नहीं होंगे और आबकारी के दोषी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक यह सख्ती केवल कागजी शेर बनकर रह जाएगी। उमरिया की जनता ढोल-नगाड़ों की आवाज से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से संतुष्ट होगी, एसडीएम अम्बिकेश प्रताप सिंह की कार्रवाई काबिले तारीफ है।

इन्दवार एवं मानपुर के गांवों में फैल रहा शराब का जाल

चिल्हारी नवभारत 14 मई। उमरिया जिले के ग्रामीण अंचलों में शराब की अवैध बिक्री और ओवररेट वसूली को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। जिले के इन्दवार एवं कंपोजिट दुकान मानपुर से संचालित शराब कारोबार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब दुकानों के संचालकों द्वारा गांव-गांव एजेंटों के माध्यम से खुलेआम पैकारी करवाई जा रही है। नियमों को दरकिनार कर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पहुंचाए जाने से सैकड़ों गांवों का प्रभावित हो रहे है।

देर रात तक हो रही शराब की अवैध बिक्री-दूसरी ओर शराब की बोतलों पर अंकित निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई गांवों में देर रात तक शराब की अवैध बिक्री हो रही है, जिससे युवाओं में शराब की लत तेजी बढ़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार कम उम्र के युवक भी आसानी से शराब तक पहुंच बना रहे हैं।

युवा नशे की गिरफ्त में-क्षेत्रवासियों का कहना है कि गांवों में बढ़ती शराबखोरी का सबसे ज्यादा असर युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। पढ़ाई और रोजगार की ओर ध्यान देने के बजाय कई युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई है कि यदि समय रहते अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो ग्रामीण समाज में अपराध, घरेलू हिंसा और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।

निष्पक्ष जांच कराने की मांग-मामले को गंभीर मानते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर राखी सहाय को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गांवों में हो रही अवैध पैकारी पर तत्काल रोक लगाई जाए, ओवररेट शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा इस कार्य में संलिप्त जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाए।

उमरिया में प्यासी जनता, कागजों में बहता पानी!

नल-जल योजना और जल जीवन मिशन पर उठ रहे सवाल

नवभारत उमरिया 14 मई। केंद्र और राज्य सरकार जहां 'हर घर जल' का सपना दिखा रही है, वहीं उमरिया जिले में जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। जिले में नल-जल योजना, जल जीवन मिशन और अन्य पेयजल योजनाओं की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आज तक जिले का एक भी गांव पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी पाइपलाइनें, बंद पड़ी पानी टंकियां, खराब हैंडपम्प और सूखी नल योजनाएं विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। लोगों का कहना है कि पीएचई विभाग केवल कागजों में योजनाओं को पूरा दिखाने में लगा है, जबकि धरातल पर जनता आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान है।

पेयजल योजना पटरी से उतरी

ग्रामीणों के अनुसार, जब से पीएचई के कार्यपालन अभियंता एचएस धुर्वे की पदस्थापना उमरिया जिले में हुई है, तब से जिले की पेयजल योजनाएं पूरी तरह पटरी से उतर गई हैं। आरोप है कि नल-जल योजना और जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी हैं। लोगों का कहना है कि कई गांवों में पाइपलाइन बिछाकर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, कहीं टंकियां बनकर बंद पड़ी हैं तो कहीं महीनों से हैंडपम्प खराब पड़े हैं।

हैंडपम्प मरम्मत के लिए ग्रामीणों से मांगे गए पैसे

सबसे गंभीर आरोप यह है कि हैंडपम्प मरम्मत जैसे कार्यों के लिए भी गरीब ग्रामीणों से पैसे मांगे जाते हैं, जबकि इन योजनाओं के रखरखाव के लिए शासन पहले से बजट जारी करता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी योजनाओं

को जनता की सुविधा के बजाय कमाई का साधन बना चुके हैं। शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता और ग्रामीणों को लगातार आश्वासन देकर टाल दिया जाता है।

पीएचई विभाग की लापरवाही निंदनीय : पाण्डेय

इस मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप पांडेय ने कहा कि पीने के पानी को लेकर जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार और पीएचई विभाग की लापरवाही निंदनीय है। पेयजल का सौदा करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी अधिकारियों पर उचित मंच पर कार्रवाई की बात मजबूती से उठाई जाएगी।

सामूहिक विवाह में 166 वर-वधु परिणय सूत्र में बंधे

सीएम राइज विद्यालय प्रांगण में समारोह आयोजित

अमरपुर नवभारत 14 मई। सीएम राइज विद्यालय प्रांगण, अमरपुर में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ।

समारोह में जनपद पंचायत समनापुर एवं अमरपुर के कुल 166 वर-वधु परिणय सूत्र में बंधे। प्रशासन द्वारा सभी युगलों को टोकन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। समारोह में नृत्य एवं गुदुम बाजा की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं तथा विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराए गए। वधुओं को सीएम राइज स्कूल अमरपुर से मुख्य समारोह स्थल तक लाया गया, जबकि मॉडल छात्रावास से बारात नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सामूहिक विवाह स्थल, सीएम राइज विद्यालय प्रांगण पहुंची।

प्रत्येक जोड़े को एक-एक अंगूठी भेंट की गई

विधायक ओमप्रकाश धुर्वे एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक जोड़े को पांच बर्तन, पांच जोड़ी वस्त्र एवं एक-एक अंगूठी भेंट स्वरूप प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक लोकनृत्य कर समारोह का उत्साहवर्धन किया।

योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान : धुर्वे

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के सम्मान एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का पवित्र बंधन है।

हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिला : कुलस्ते

सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। सांसद कुलस्ते ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय एवं समृद्ध जीवन की कामना की।

पशु चिकित्सालय की लापरवाही उजागर, इमरजेंसी पट्टी तक नहीं

घायल पशुओं के इलाज पर संकट, नगरवासियों ने विभाग पर लगाया उदासीनता का आरोप

शहपुरा नवभारत 14 मई। शहपुरा स्थित पशु चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नगरवासियों ने अस्पताल प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही एवं उदासीनता का आरोप लगाया है।

आरोप है कि अस्पताल में इमरजेंसी उपचार के लिए आवश्यक मलहम-पट्टी तक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण घायल पशुओं को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा। जानकारी के अनुसार, हाल ही में एक घायल पशु को उपचार के लिए शहपुरा पशु चिकित्सालय लाया गया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर द्वारा यह कह दिया गया कि अस्पताल में ड्रेसिंग के लिए पट्टी उपलब्ध नहीं है। यह सुनकर पशुपालक और नगरवासी हैरान रह गए।

आपातकालीन स्थिति में पशुओं का कैसे होगा इलाज-लोगों का कहना है कि जब अस्पताल में प्राथमिक उपचार की मूलभूत सामग्री ही नहीं होगी, तो आपातकालीन स्थिति में पशुओं का इलाज आखिर कैसे किया जाएगा। नगरवासियों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से अस्पताल में मलहम-पट्टी और ड्रेसिंग सामग्री खत्म पड़ी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इसकी पूर्ति कराने की जरूरत नहीं समझी।

दुर्घटनाओं से घायल पशुओं की संख्या बढ़ रही-भीषण गर्मी और सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों के बीच घायल पशुओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अस्पताल में इमरजेंसी सुविधा का अभाव गंभीर चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि शासन द्वारा पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, फिर भी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।

मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग-लोगों का कहना है कि यदि किसी गंभीर रूप से घायल पशु को तत्काल उपचार की आवश्यकता पड़े, तो अस्पताल की यह लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ सकती है। नगरवासियों ने पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और अस्पताल में तत्काल आवश्यक दवाइयां एवं ड्रेसिंग सामग्री

उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं, इस पूरे मामले ने शहपुरा पशु चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम चल रहा एक के अस्सी का खेल, लालच में लुट रहे गरीब

अमरपुर नवभारत 14 मई। अमरपुर जनपद मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों अवैध सट्टा कारोबार तेजी से फैलता नजर आ रहा है।

क्षेत्र के ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि 'एक का अस्सी' जैसे लालच देकर संचालित किया जा रहा सट्टा बाजार गरीब, मजदूर और निम्न आय वर्ग के लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने का माध्यम बनता जा रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभागों द्वारा अब तक इस गंभीर सामाजिक समस्या पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अवैध कारोबार संचालित करने वालों के हौसले बुलंद हैं।

क्षेत्र में कई प्रकार के सट्टा बाजार हैं सक्रिय-ग्रामीणों के अनुसार अमरपुर क्षेत्र में कई प्रकार के सट्टा बाजार सक्रिय हैं, जिनमें गली, दिसावर, फर्रुखाबाद, राजधानी, गाजियाबाद, कल्याण, मेन कल्याण, मिलन डे और मिलन नाइट जैसे नाम प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। बताया जा रहा है कि इन बाजारों में एक रुपये के बदले अस्सी रुपये मिलने का लालच देकर लोगों को दांव लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

मजदूर व छोटे किसान हो रहे प्रभावित-शुरुआत में छोटी रकम लगाने वाले लोग धीरे-धीरे अधिक धन लगाने लगते हैं और अंततः आर्थिक नुकसान उठाते हैं। सबसे अधिक प्रभावित दैनिक मजदूरी करने वाले, छोटे किसान और गरीब परिवार बताए जा रहे हैं, जिनकी सीमित आय का बड़ा हिस्सा इस अवैध जुए में बर्बाद हो रहा है।

गांव-गांव में कुछ एजेंट सक्रिय हैं-स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि गांव-गांव में कुछ एजेंट सक्रिय हैं, जो रोजाना पर्ची काटकर सट्टा खिलाते हैं। सुबह और शाम तय समय पर नंबर खुलने की बात कहकर लोगों से रकम वसूली जाती है। इससे युवाओं में भी गलत प्रवृत्ति बढ़ रही है और आसानी से पैसे कमाने की चाहत उन्हें इस अवैध कारोबार की ओर आकर्षित कर रही है।

अवैध सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग-स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाए। गांव-गांव में सक्रिय एजेंटों की पहचान कर कार्रवाई की जाए तथा आम लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाए। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई करे, तो क्षेत्र में फैल रहे इस अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सकती है।

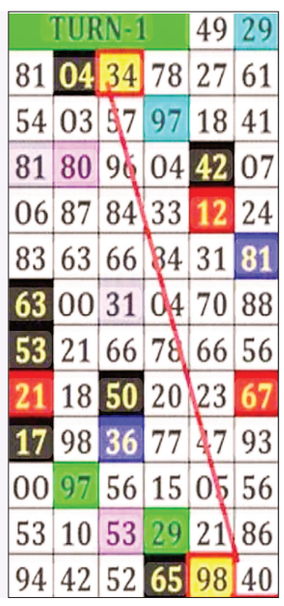

चर्चा | भारतीय किसान संघ की बैठक में किसानों की समस्याओं और मांगों पर की गई चर्चा

किसानों को समय पर बिजली, पानी, खाद व बीज उपलब्ध हो : साहू

शहपुरा नवभारत 14 मई। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जुड़े कई सुझाव और मांगें रखी गईं।

बैठक में कृषि विभाग से खरीफ सीजन के लिए मक्का, धान, अरहर, सोयाबीन, कोदो-कुटकी सहित अन्य बीजों की पर्याप्त उपलब्धता 15 जून तक सुनिश्चित करने तथा वर्षा पूर्व किसानों को वितरण कराने की मांग की गई। किसानों ने धान और गेहूं उपार्जन सीमा बढ़ाने, सिंचित भूमि का सही गिरदावरी रिकॉर्ड दर्ज करने और फसल कटाई प्रयोगों में किसान संघ को शामिल करने की मांग भी रखी। खाद एवं उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने तथा लंबित अनुदान राशि किसानों के खातों में जमा कराने की बात कही गई।

स्थाई ढांचों की संख्या बढ़ाने की मांग

उद्यानिकी विभाग से प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु स्थाई ढांचों की संख्या बढ़ाने, कृषि उपकरणों की मूल्य विसंगतियों में सुधार तथा कृषक भ्रमण योजनाओं में पारदर्शिता लाने की मांग की गई। पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सालयों में दवाइयों की उपलब्धता और समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

जर्जर विद्युत लाइन सुधारने की मांग

विद्युत विभाग से कम वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मरों को बदलने, ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर विद्युत लाइन सुधारने, जले ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे में बदलने तथा किसानों को 5 रूपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। शहपुरा एवं मेंहदवानी क्षेत्र में बार-बार बिजली बंद होने की समस्या भी उठाई गई। जल संसाधन विभाग के संबंध में किसानों ने जिले के बांधों और नहरों की समय पर मरम्मत, गेट सुधार तथा खेतों तक सिंचाई पानी पहुंचाने की मांग की।

जलाशयों से संबंधित समस्याओं को रखा गया

समनापुर, भाजीटोला, मोहदा और चैरा जलाशयों से संबंधित समस्याओं को भी प्रमुखता से रखा गया। पीएचई विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजनाओं में गुणवत्ताहीन कार्यों की शिकायत करते हुए बंद पड़ी नल-जल योजनाओं की जांच और सुधार की मांग की गई। सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग के संबंध में किसानों ने पासबुक प्रिंटिंग, ऋण जमा प्रक्रिया और नवीन लेम्पस संचालन में सुधार की आवश्यकता बताई।

अतिक्रमण हटाने की मांग की गई

राजस्व विभाग से गिरदावरी सुधार, सीमांकन, फौती नामांतरण, सार्वजनिक भूमि संरक्षण और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। साथ ही किसानों के खेतों के पारंपरिक रास्तों को नक्शों में दर्ज करने तथा राजस्व जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई। बैठक में वन विभाग से जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा तथा फेंसिंग पर 80 प्रतिशत अनुदान देने की मांग रखी गई।

इनकी रही उपस्थिति

बैठक में कृषि उपसंचालक संजय जोशी, उपसंचालक पुशपालन एवं डेयरी विभाग एच पी शुक्ला, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू, जिला कोषाध्यक्ष विवेकानंद साहू, उपाध्यक्ष भानसिंह मरकाम, विपणन प्रमुख खिलपत सिंह गौतम, सदस्य खूबचंद साहू, डिंडौरी तहसील अध्यक्ष खमोद चंदेल, बजाग तहसील अध्यक्ष आशाराम यादव, शहपुरा तहसील उपाध्यक्ष जगदीश साहू, सदस्य मटरू दादा, नंद किशोर झारिया आदि उपस्थित रहे।

सड़क सुधार को लेकर ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम

दो घंटे तक बाधित रहा यातायात

करंजिया, नवभारत 14 मई। जनपद पंचायत मुख्यालय करंजिया के पास स्थित ग्राम नदिया टोला के ग्रामीणों ने बुधवार सुबह सड़क की बदहाली से नाराज होकर जबलपुर-अमरकंटक हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। करीब दो घंटे तक हाईवे जाम रहने से दोनों ओर छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे निर्माण के बाद से ही गांव तक पहुंचने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह जर्जर है। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं। कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जिसके चलते ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

प्रशासन ने दिया आश्वासन

सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार आशुतोष मिश्रा एवम थाना प्रभारी श्याम सुंदर उसराठे मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें शांत कराया और भरोसा दिलाया कि सड़क सुधार, मरम्मत और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।

अन्य मांगें भी रखीं गईं

ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के साथ-साथ हाईवे पर यात्री प्रतीक्षालय बनाने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी। तहसीलदार ने कहा कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।